भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2820

जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने हेतु उठाए गए कदम

2820. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जोकि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और शोषण से जुड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकरा की बच्चों को सोशल मीडिया ऐप सहित हानिकारण ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सामग्री तक पहुंच को रोकने के लिए ठोस उपाय करने की मंशा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उपाय कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को देश में पोर्नोग्राफी दिखाने वाली वेबसाइटों, ऐप्स आदि के माध्यम से की गई पोस्ट आदि की समीक्षा करने और विरुद्ध जवाबदेही तय करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):** सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या सूचना से मुक्त है, विशेष रूप से जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नाबालिगों के शोषण का कारण बन सकता है।

<u>डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री से बचने के लिए कानूनी ढांचा</u>

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000

आईटी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से बचने के लिए एक सख्त ढांचा तैयार किया है।

यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों पर स्पष्ट दायित्व लगाता है।

आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे पहचान की चोरी (धारा 66ख), प्रतिरूपण (धारा 66घ), गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66ड़), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने (धारा 67, 67क, 67ख) के लिए सजा प्रदान करता है।

यह पुलिस को अपराधों की जांच करने (धारा 78), सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने और संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार देता है (धारा 80)।

आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर उचित परिश्रम दायित्वों को डालते हैं, और उन्हें इन दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता होती है ताकि गैरकानूनी सामग्री की होस्टिंग या प्रसारण को रोका जा सके।

आईटी नियम, 2021 के तहत प्रमुख प्रावधान:

प्रावधान	**विवरण**
प्रतिबंधित जानकारी नियम 3(1)(ख) के तहत	अन्य बातों के अलावा, जानकारी/सामग्री को होस्ट करने, संग्रहीत करने, प्रसारित करने, प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने को प्रतिबंधित करता है: • अश्लील, अश्लील, दूसरे की गोपनीयता पर आक्रामक, लिंग के आधार पर अपमान या उत्पीड़न, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या नफरत या हिंसा को बढ़ावा देना; • बच्चे के लिए हानिकारक; • धोखा देता है या गुमराह करता है, जिसमें डीपफेक भी शामिल है; • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित दूसरों का प्रतिरूपण करता है; • राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है; • किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करता है।
उपयोगकर्ता जागरूकता दायित्व	मध्यस्थों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सामग्री हटाने, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है।
सामग्री हटाने में जवाबदेही	मध्यस्थों को अदालत के आदेशों, सरकार से तर्कसंगत सूचना या उपयोगकर्ता की शिकायतों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए।
शिकायत निवारण	• शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए मध्यस्थ • 72 घंटों के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के माध्यम से शिकायतों को हल करने का आदेश। • गोपनीयता का उल्लंघन करने, व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने या नग्नता दिखाने वाली सामग्री को ऐसी किसी भी शिकायत के खिलाफ 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
शिकायत अपीलीय समितियां (जीएसी) तंत्र	यदि मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है तो उपयोगकर्ता www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

सरकारी एजेंसियां को मध्यस्थों द्वारा सहायता	मध्यस्थों को अपने नियंत्रण में जानकारी प्रदान करनी चाहिए या पहचान सत्यापन के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए या साइबर सुरक्षा घटनाओं सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के लिए।
महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ (अर्थात्, भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थ)	• मैसेजिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले एसएसएमआई को कानून प्रवर्तन को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के प्रवर्तकों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। • एसएसएमआई गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करते हैं।

आईटी नियम, 2021 में प्रदान किए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में मध्यस्थों की विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तीसरे पक्ष की जानकारी से अपनी छूट खो देते हैं।
वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) और नियम 2025 ऑनलाइन बच्चों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
यह बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य करता है और बच्चों के प्रति ट्रैकिंग, व्यवहार निगरानी या लक्षित विज्ञापन जैसे उनकी भलाई के लिए हानिकारक प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है।
यह व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को भी प्रतिबंधित करता है जो बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक है या इसमें ट्रैकिंग, व्यवहार निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

बीएनएस, 2023 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए अपराधों सहित ऑनलाइन नुकसान, अश्लीलता, गलत सूचना और अन्य साइबर-सक्षम अपराधों से जुड़े अपराधों को संबोधित करता है।

- अश्लील कृत्यों और गीतों (धारा 296), इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी किसी भी सामग्री के प्रदर्शन सहित अश्लील सामग्री की बिक्री जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है (धारा 294)
- धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कार्य को दंडित करके गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकना है जो सार्वजनिक शरारत या भय पैदा कर सकते हैं।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

पॉक्सो अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के प्रावधानों का प्रावधान करता है।

- धारा 13 यौन संतुष्टि के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के मीडिया में बच्चे के उपयोग को अपराध बनाती है - चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित या प्रसारित हो।
- धारा 14 में कम से कम पांच साल के कारावास की सजा और पहले अपराध के लिए जुर्माना निर्धारित किया गया है। बाद की दोषसिद्धि के लिए, सजा कम से कम सात साल के कारावास और जुर्माने तक बढ़ जाती है।

- धारा 15 बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने, भंडारण करने या रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए एक श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली निर्धारित करती है

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, वयस्क फिल्मों सहित फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है।

सीबीएफसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-वयस्कों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त मानी जाने वाली फिल्मों को केवल वयस्क दर्शकों के लिए प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाएगा।

साइबर अपराधों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय:

समन्वित तरीके से ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित सहित कई अन्य उपाय भी किए हैं

- गृह मंत्रालय बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों को सभी साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) का संचालन करता है
- बाल यौन शोषण सहित साइबर अपराध के खिलाफ समन्वित और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की गई है
- साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
- सरकार समय-समय पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को इंटरपोल से प्राप्त जानकारी के आधार पर ब्लॉक करती है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से रूट की जाती है
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (यूके) और प्रोजेक्ट अरचिन्ड (कनाडा) जैसे वैश्विक डेटाबेस का उपयोग करके सीएसएएम वेबसाइटों को गतिशील रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है
- आईएसपी को यह भी सलाह दी गई है कि वे माता-पिता के नियंत्रण फिल्टर को बढ़ावा दें और अंतरराष्ट्रीय गेटवे के माध्यम से पहचानी गई सीएसएएम वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करें
- साइबर सुरक्षा पर जन जागरूकता को @साइबरदोस्त, रेडियो अभियान और छात्रों और किशोरों के लिए हैंडबुक के प्रकाशन जैसी पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है
- एनसीआरबी (एमएचए) और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर टिपलाइन रिपोर्ट साझा करने में सक्षम बनाता है, जिसे त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित किया जाता है।

******